उत्तर प्रदेश
ई-संदेश
29 अगस्त, 2018 • वर्ष 1, अंक 32

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, के.जी.एम.यू. लखनऊ में राज्य पोषण मिशन के दौरान बच्चों से मिलते हुए

- अब तक के सबसे बड़े अनुपूरक बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल
- उत्तर प्रदेश को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा अधिक जल
- मुख्यमंत्री जी ने जाना बाढ़ पीडितों का हाल
- यू.पी. को पर्यटन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान दिलाने हेतु कार्य कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री
- 6 विभागों का साझा प्रयास : पोषण मिशन व सुपोषण स्वास्थ्य मेला
- रक्षाबंधन पर बहनों को बसों मे नि:शुल्क यात्रा की सौगात

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

अब तक के सबसे बड़े अनुपूरक बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि विकासपरक योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिले और प्रदेश प्रगति के नये मानक गढ़ने में सफल हो। उनके इस संकल्प की छाप राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत 34833.244 करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट में दिखाई दी। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है।

किसानों का खास ख्याल

इस अनुपूरक बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट में जहां एक ओर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के लिए 5,535 करोड़ रूपये और कर्फमाफी के लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को समझते हुए बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया, तो छुट्टा पशुओं की समस्या के निवारण हेतु संसाधनों की व्यवस्था की गई।

डिफेन्स कॉरिडोर हेतु धनराशि

बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को संजोने हेतु पांच परियोजनाओं के अन्तर्गत 25 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। डिफेन्स कॉरिडोर को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के साथ विकसित करने हेतु 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा क्षेत्र का भी रखा ध्यान

सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व समतुल्य संवर्ग को सातवां वेतनमान देने हेतु 921.5 करोड़ की व्यवस्था की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाएं देने के लिए 700 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 44 नए इंटर कॉलेज और 42 महाविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट में 25–25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

कुल मिलाकर इस बजट में समाज के हर वर्ग की प्रगति हेतु सरकार के सार्थक प्रयासों की सोच परिलक्षित होती है। सरकार ने जिस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल अपने बजट में रखा है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ■

चिकित्सा

05 करोड़ : बलरामपुर जिले में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर की स्थापना के लिए।

3.4 करोड़ : केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली के संचालन के लिए।

02 करोड़ : केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट फॉर बर्न इंजरी के संचालन के लिए।

4.9 करोड़ : राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ के नवनिर्मित सौ बेड के यूनानी अस्पताल में सजावट एवं उपकरणों के लिए।

उद्योग

01 हजार टोकन मनी : संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के लिए।

500 करोड़ : बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए।

100 करोड़ : 21 से 23 जनवरी 2019 को प्रस्तावित प्रवासीय भारतीय दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

गन्ना विकास

4000 करोड़ : प्रदेश की चीनी (निजी एवं निगम क्षेत्र) पर पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के लिए सॉफ्ट लोन देने के लिए।

1010 करोड़ : उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। इसमें पेराई सत्र 2016-17 के बकाया मूल्य भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम 125 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शामिल है।

500 करोड़ : पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

40.5 करोड़ : सौर ऊर्जा नीति के तहत उत्पादित बिजली को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने के लिए प्रोत्साहन राशि।

1 करोड़ : बहराइच जिले में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा आरओ वाटर प्लांट की स्थापना।

1 करोड़ : लखनऊ में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मदद के लिए।

40 लाख : सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में ई-ऑफिस के लिए एवं कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों के लिए 1.53 करोड़ रुपये।

महिला एवं बाल कल्याण

8.86 करोड़ : किशोरी बालिका योजना लागू करने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाएंगे मेडिसिन किट।

173 करोड़ : पोषण अभियान (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम) के लिए।

623 करोड़ : आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के लिए।

40 करोड़ : आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन के लिए।

अनुपूरक बजट में खास

न्याय विभाग

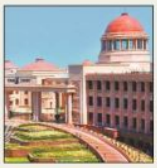

28.4 लाख : हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में बैटरी चालित वाहन की खरीद के लिए।

5 करोड़ : हाईकोर्ट इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में ई-कोर्ट की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

10 करोड़ : प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए अंतरिम सहायता के लिए विभिन्न लेखा शीर्षक के तहत बजट की जरूरत।

22.7 लाख : सांसदों एवं विधायकों को शीघ्र निस्तारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के संचालन के लिए अतिरिक्त जरूरत।

10 करोड़ : विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ताओं के वेतन व फीस के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

1.7 करोड़ : न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में साउंड सिस्टम के लिए।

13 करोड़ : हाईकोर्ट, इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त जरूरत।

89 लाख : उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत के अधिकारियों व कर्मचारियों के एरियर के लिए।

10 करोड़ : उप्र न्यायिक अधिकारी कल्याण कोष के कार्पस फंड के लिए।

लोक निर्माण

(राज्य संपत्ति निदेशालय)

1.34 करोड़ : राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के आवासों के बिजली बिल के लिए।

1.25 करोड़ : विभिन्न विभागों/इकाइयों एवं कैम्प कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की मजदूरी के लिए।

2.76 करोड़ : सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के सरकारी आवासों के विद्युत देय हेतु।

1.07 करोड़ : बटलर पैलेश कालोनी में नवनिर्मित श्रेणी-5 के प्रथम बहुखंडीय भवन, सचिवालय कालोनी महानगर स्थित टाइट-2 एवं टाइप-3 के नवनिर्मित बहुखंडीय भवन एवं तिलक मार्ग डालीबाग, लखनऊ में नवनिर्मित बहुखंडीय भवन में विभिन्न विद्युत उपकरणों के संचालन के लिए।

9.49 करोड़ : विधायकों को आवंटित आवासों के बिजली बिल के लिए।

41 लाख : नवनिर्मित बहुमंजिला विधायक निवास, दारुलशफा के विभिन्न विद्युत उपकरणों के लिए।

राजस्व

(दैवीय विपत्तियों पर राहत)

301 करोड़ रुपये : बाढ़ के प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए।

शिक्षा

1.53 करोड़ : सैनिक स्कूल लखनऊ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान के लिए।

4 करोड़ : राष्ट्रीय सेना छात्र दल एनसीसी निदेशालय के अधिष्ठान के लिए।

25 करोड़ : विभिन्न जिलों में राजकीय इंटर कालेज की स्थापना के लिए।

47 करोड़ : गोरखपुर विवि को 28 करोड़, संपूर्णानंद संस्कृत विवि वाराणसी को 14 करोड़ एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को 5 करोड़ वेतन के लिए।

921 करोड़ : राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक व समतुल्य संवर्ग में सातवें वेतनमान के लिए।

5 करोड़ : अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डीएवी कालेज कानपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए राजस्व पक्ष में और पूंजीगत पक्ष में 1 हजार रुपया टोकन-मनी का प्रावधान।

30 लाख : एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए।

25 करोड़ : नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना को।

36 लाख : बीबीएयू लखनऊ के लिए अर्जित भूमि के प्रतिकर की बढ़ी राशि के लिए।

91.7 लाख : लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी स्थित कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन के अधिष्ठान के लिए।

5 करोड़ : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नियामक कार्यालय इलाहाबाद हेतु टीईटी चयन, बीटीसी चयन एवं बीटीसी परीक्षा कराये जाने के लिए।

नगर विकास

800 करोड़ : कुंभ मेला 2019 इलाहाबाद के आयोजन के लिए।

25 करोड़ : नगरीय पेयजल योजना के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए।

20 करोड़ : नगर निकायों में कान्हा गोशाला की स्थापना के लिए।

20 करोड़ : राजीव आवास योजना के लिए।

15 करोड़ : नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों, प्रदर्शिनी स्थलों व सभागार के विकास के लिए।

नियोजन

03 करोड़ : गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

7.5 लाख : स्टेट स्ट्रैटिजिक प्लान (एसएसएस) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

9.7 करोड़ : बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।

750 करोड़ : त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए।

विधानसभा सचिवालय

12.57 लाख : विधान भवन मुख्य भवन के समस्त तलों में स्थापित एड्रेसेबुल एवं फायर उपकरणों का बदलाव एवं जीर्णोद्धार करने के लिए ।

1 करोड़ : विधान भवन स्थित पुस्तकालय में सीसी टीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए।

50.93 लाख : विधानसभा मंडप में एवी रिकार्डिंग सिस्टम प्रणाली के लिए।

50.32 लाख : विधानसभा परिसर में वुडेन वर्क पर अग्नि प्रतिरोधी पेन्ट लगवाने के लिए।

17.92 लाख : मुख्य भवन कक्षा संख्या 8 के हाल में सभापति एवं उनके स्टाप के केबिन निर्माण हेतु।

24.40 लाख : पुस्तकालय के प्रशासनिक खंड के सामने स्थित बरामदे का आधुनिकीकरण ।

68.36 लाख : राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार में वॉल पैनलिंग तथा अन्य सिविल तथा विद्युत संबंधी कार्यों के लिए।

1.75 करोड़ : मंडप में स्थापित डिजिटल कांफ्रेंस सिस्टम और वीडियो वाल्स के विस्तार के लिए।

ग्राम्य विकास

252 करोड़ : विधायक निधि के लिए।

131 करोड़ : स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना के लिए।

100 करोड़ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अवशेष मानदेय के लिए।

75 करोड़ : बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के लिए।

39.5 करोड़ : मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के लिए।

पंचायतीराज

3907 करोड़ : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण ।

2500 करोड़ : 14वें वित्त आयोग में प्रावधानित राशि में से आहरण की प्रतिपूर्ति के लिए।

200 करोड़ : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत पंचायतों एवं ग्रामसभा की क्षमता बढ़ाने के लिए।

11 करोड़ : प्रादेशिक विकास दल योजना के तहत युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित के लिए।

10 करोड़ : जिला पंचायतों में कांजी हाउस के लिए।

उत्तर प्रदेश को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा अधिक जल

हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तथा जल संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी संसाधनों के उचित क्रियान्वयन तथा वर्षा जल के समुचित भण्डारण के अभाव में पानी की समस्या सामने आती है। किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु भरपूर पानी नहीं मिल पाता है, वहीं महानगरों तथा गांवों में लोगों को पीने हेतु पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पाता था। परन्तु अब केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने हेतु समुचित कदम उठाये हैं।

यमुना नदी पर बनेगी लखवाड़ बाँध परियोजना

इसी क्रम में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखण्ड में यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बॉध बहु उद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 6 बेसिन राज्यों के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये।

उत्तर प्रदेश सहित छः राज्यों के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में करीब चार हजार करोड की लखवाड़ बॉध बहु उद्देशीय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जी, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये।

गर्मियों में नहीं होगी पानी की समस्या

इस अवसर पर नितिन गडकरी जी ने कहा कि 6 राज्यों के बीच जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये है, वह सभी के लिए बहुत उपयोगी है। गर्मियों में अब हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की दिक्कत नही होगी। गर्मियों में जब यमुना में पानी कम होगा, तब इस बॉध का पानी काम आयेगा।

42000 हेक्टेयर अधिक भूमि का होगा सिंचन

इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। एक ओर जहॉ हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, वहीं दूसरी तरफ एक तिहाई आबादी पेयजल को तरस रही है। परियोजना के पूरी हो जाने पर सिंचाई व पेयजल के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। 42000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान को पेयजल के लिए अधिक जल मिलेगा। ■

4000 करोड की इस परियोजना में 90 प्रतिशत धनराशि केन्द्र की सरकार तथा 10 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित राज्य वहन करेंगे।

यू.पी. को पर्यटन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान दिलाने हेतु कार्य कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध राज्य है, परन्तु अभी तक इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। वर्तमान राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। पर्यटन के लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और सम्पर्क मार्गो की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वर्तमान सरकार तेजी से काम कर रही है। अर्थव्यवस्था के विकास से पर्यटन की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जो पर्यटन के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार लखनऊ में उ.प्र. पर्यटन विभाग तथा फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित **'उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट–2018'** के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक पर्यटन सर्किटों जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि का विकास करके इनकी अवस्थापना सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद बौद्ध धर्म स्थलों का विकास किया जाएगा, ताकि बौद्ध अनुयायियों के अलावा अन्य पर्यटक भी इनकी ओर आकर्षित हो सकें। ■

पर्यटन के लिए सबसे आवश्यक तत्व आवागमन की बेहतर सुविधायें है। जेवर में स्थापित किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर्यटकों को काफी सुविधा होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में भी कार्य चल रहा है।

राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं। केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रासाद योजना तथा स्वदेश दर्शन योजना संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के हर शहर में पर्यटन के पर्याप्त अवसर हैं। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से देश का सबसे सुरक्षित स्थल बन गया है, जो पर्यटन के लिए सबसे आवश्यक है।

आगामी दिसम्बर माह में प्रयाग में होने वाले कुम्भ के लिए विश्व के 192 देशों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारीगणों को आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2019 में जनवरी से मार्च के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न होने वाले विश्व के इस विशालतम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समागम में करीब 12 करोड़ लोगों के आने की सम्भावना है। साथ ही 20 से 23 जनवरी, 2019 के दौरान वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें करीब 6000 प्रवासी भारतीय प्रतिभाग करेंगे। इनके माध्यम से विश्व में उत्तर प्रदेश के पर्यटन को एक नई पहचान मिल सकेगी।

–योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री जी ने जाना बाढ़ पीडितों का हाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता के दुःख–दर्द में सदैव उनकी सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। प्रदेश के कई जिले बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उनकी हरसंभव सहायता हेतु बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने लखीमपुर, गोण्डा, बाराबंकी आदि जिलों का दौरा कर जनता को सहायता सामग्री का वितरण किया तथा उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जा रही सहायता सेवाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

कृषि भूमि को बचाने पर जोर

मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जहां पर नदियां कृषि भूमि का कटान कर रही हैं और फसलें नष्ट हो रही हैं, वहां पर बैम्बू क्रेट लगाने में तेजी लायी जाएगी, जिससे कृषि भूमि को बचाया जा सके। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित की गई बाढ़ चौकियां 24 घण्टे सक्रिय रहेंगी। कटान के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी की जाएगी। बाढ़ चौकियों पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। सिंचाई विभाग के अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वे कटान से प्रभावित गांवों में कटान से निपटने के लिए अविलम्ब प्रभावी कार्रवाई करें।

बाढ़गस्त क्षेत्रों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग वहां से नहीं हटना चाहते, उन्हें राहत सामग्री वहीं पर पहुंचायी जा रही है।

आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था

बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए प्रभावित जनपदों के सिंचाई विभाग के अधिकारी, बाढ़ की समस्या कम होने तक, अवकाश पर नहीं जायेंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के कार्यों में और अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिए गए हैं और इस आपदा से निपटने के लिए जनपदों को पर्याप्त धनराशि भी दी गई है। बाढ़ नियंत्रण व राहत कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु तत्पर है सरकार

राज्य सरकार बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को 10–10 किलो चावल–गेहूं के अलावा केरोसिन, माचिस, नमक, मोमबत्ती तथा तिरपाल राहत सामग्री के रूप में उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से मृत्यु होने की दशा में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रभावितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी ढंग से किये जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। राज्य सरकार विपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ है और उनकी हर सम्भव सहायता कर रही है। ■

अपने मूल्यों एवं आदर्शों के साथ अटल जी सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे : मुख्यमंत्री

अटल जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा स्थान बनाया कि भारत के लोग उन्हें महानायक के रूप में मानते हैं। वर्ष 1957 के लोक सभा चुनाव में अटल जी बलरामपुर से निर्वाचित हुए। आगे चलकर वे देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने मूल्यों और सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति की। वे भारतीय राजनीति में अपने सकारात्मक योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे।

यह विचार राज्यपाल राम नाईक जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

असाधारण है अटलजी की लोकप्रियता : गृहमंत्री

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति और राजनीतिज्ञ के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लोकप्रियता हासिल की, वह असाधारण है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही अटल जी की प्रतिभा के सभी लोग कायल हो गए थे और यह मानने लगे थे कि यह युवा सांसद एक दिन प्रधानमंत्री अवश्य बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के उपरान्त अटल जी ने अपने कार्यों, निर्णयों तथा कूटनीति से विश्व में भारत का मस्तक ऊँचा किया। अटल जी एकदम निर्भीक व्यक्तित्व वाले राजनीतिज्ञ थे। साथ ही, वे अत्यन्त विनम्र भी थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

विरोधी भी हो जाते थे अटलजी से सहमत

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ने अटल जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली थे कि वे हमारे बीच मौजूद थे। अटल जी अपने विरोधियों से भी अपनी बातें मानने के लिए सहमति बना लेते थे।

धरोहर है अटलजी की प्रेरणा

बिहार के राज्यपाल लालजी टण्डन जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका अटल जी के साथ लम्बा साथ रहा। उन्होंने अटल जी से बहुत कुछ सीखा। आज चारों दिशाओं में अटल जी की कीर्ति फैली हुई है। अटल जी की प्रेरणा उनके शेष जीवन में उनकी धरोहर रहेगी। ■

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों के राप्ती नदी में विसर्जन के अवसर पर दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि वाजपेयी जी पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी, राजनेता, राष्ट्रध्यक्ष के रूप में अनुकरणीय हैं। आजादी के 70 वर्षों के कार्यकाल में राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अटल जी से प्रभावित रहे हैं। देश में संचार क्रान्ति लाने में भी अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान है।

अटलजी ने सदैव विकास की राजनीति की। उन्होंने देश की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन्होंने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क तैयार करवाया। आज अटल जी की इस दूरदृष्टि का फायदा देश के गांवों को मिल रहा है। अटल जी दूरदृष्टा थे और प्रगति के लिए तकनीक और ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता को उन्होंने पहले ही पहचान लिया था। इसलिए अटल जी ने तकनीक का प्रयोग विकास और समृद्धि के लिए करने पर बल दिया।

-योगी आदित्यनाथ

6 विभागों का साझा प्रयास
पोषण मिशन व सुपोषण स्वास्थ्य मेला

कुपोषण व एनीमिया के खिलाफ जंग : मुख्यमंत्री

डी.बी.टी. से जोड़ा जायेगा पोषण मिशन, सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी राशि

सशक्त भारत का रास्ता बेहतर स्वास्थ्य से होकर गुजरता है। इसलिए प्रदेश में छह विभाग मिलकर पोषण अभियान चला रहे हैं। अगर शासन की योजनाएं ईमानदारी से नीचे तक पहुंचा दी जाये तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मर सकता।

यह विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में पोषण अभियान और सुपोषण स्वास्थ्य मेला के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुपोषित बच्चे को स्वस्थ रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। स्कूल चलो अभियान का नतीजा है कि प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.77 करोड़ हो चुकी है। स्कूलों में स्थायी शिक्षकों द्वारा अपने स्थान पर पढ़ाने वाले शिक्षक (प्रॉक्सी शिक्षक) रखने की व्यवस्था पर सख्ती से रोक लगी है।

इस पोषण अभियान का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, बौनापन और एनीमिया की स्थिति में सुधार है। इसके अतिरिक्त 15 से 49 वर्ष की किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया की समस्या में कमी लाने के साथ ही जन्म के समय बच्चों के कम वजन की स्थिति में प्रति वर्ष 2 से 3 प्रतिशत की कमी लाना है। राज्य सरकार ने प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रदेश में कुल 21 हजार 730 उपकेंद्रों पर स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस की ब्रांडिंग करते हुए 'सुपोषण स्वास्थ्य मेले' के आयोजन का निर्णय लिया है।

रक्षाबंधन पर बहनों को बसों मे नि:शुल्क यात्रा की सौगात

प्रदेश में बहनों को मिली राखी की सौगात

रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं ने की नि:शुल्क बस यात्रा

हर श्रेणी की बसों में महिलाओं ने की नि:शुल्क यात्रा, जताया मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 26 अगस्त, 2018 को रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। इसके अंतर्गत निगम बसों में 25 अगस्त की मध्य रात्रि 12:00 बजे से 26 अगस्त की मध्य रात्रि 12:00 बजे के मध्य (24 घंटे के लिए) निगम की सभी प्रकार की बसों में महिला यात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने पर उनको नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के समस्त मार्गों पर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत 24 अगस्त से 29 अगस्त तक अतिरिक्त बसें संचालित की गई। इस अवधि मे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि प्रमुख नगरों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए परिवहन निमग द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बहनों को दिया रक्षाबंधन पर नि:शुल्क यात्रा का उपहार

बसों की विशेष व्यवस्था के लिए परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई तथा नि:शुल्क बस यात्रा करने वाली महिलाओं ने इस निर्णय हेतु मुख्यमंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा की और सबने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में रक्षाबंधन पर एक यादगार तोहफा दिया है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी